

अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2017 अनवानी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी  
वीपीओ धानौट वाया रेत, तहसील शाहपुरा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश बनाम  
लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर, घड़साना



20-12-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार के डाक से प्राप्त प्रा0 पत्र दिनांक 25.11.17 व 07.12.17 शामिल पत्रावली किये गये। उपखण्ड अधिकारी घड़साना का मेल पर प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 2646 दिनांक 18.12.17 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:-

मैंने मेनेजमेंट आफ पौंग बांध विस्थापित, सराय सखी रोड, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (आवेदन पत्र की प्रति सलंगन है) के लिए 17.08.2017 को एक आवेदन किया था लेकिन मेरे आवेदन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी सन्दर्भ में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली को 12.09.2017 को भी आवेदन (प्रति सलंगन) किया गया है एवं जिसकी प्रति आपकी सेवा में भी पृष्ठांकित की गई है। इसके संबंध में कृपया निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:-

1. कृपया मेरे आवेदन पर दैनिक प्रगति बताएं।
2. कृपया उन कर्मचारियों के नाम और पते बताएं जिनके पास उक्त अवधि में मेरी अर्जी पड़ी रही है। कृपया बताएं किस अधिकारी के पास किस अवधि तक वह पड़ी रही और कर्मचारी ने उस अवधि में उस पर क्या कार्यवाही की।
3. कृपया इस बात का प्रमाण दे कि कार्यालय ने उन प्रत्येक कर्मचारियों के पास मेरा आवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ और किस तारीख को प्रेषित किया गया।
4. आपके नियमों का नागरिक चार्टर या किसी, अन्य प्रदेश के अनुसार इस तरह के मामले पर कितने दिन तक कार्यवाही की जानी चाहिए और हल किया जाना चाहिए। कृपया इन नियमों की प्रति प्रदान करें।
5. उपर्युक्त कर्मचारियों ने क्या इन नियमों में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं किया है, क्या ये कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करने के दोषी हैं, और इस तरह आचरण के लिए दोषी हैं कृपया उनके आचरण नियमों की एक प्रति प्रदान करें जिन का उन्होंने उल्लंघन किया है।
6. इन कर्मचारियों ने मुझे गम्भीर मानसिक आघात पहुंचाया है और मैं इधर-उधर भटकता फिरा हूँ। क्या ये कर्मचारी जनता को मानसिक परेशानी देने के प्रति दोषी हैं।
7. उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने और जनता को मानसिक यंत्रणा देने के कारण इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है।
8. मेरी समस्या का हल अब कौन करेगा।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 2646 दिनांक 18.12.17 के साथ प्राप्त पत्र संख्या 1889 दिनांक 04.09.17 के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:-

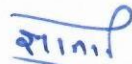
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पौंग बांध विस्थापितों के लिए बनी हुई सराय सखी रोड़ घड़साना के सम्बंध में सूचना चाही गई है इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त सराय से सम्बंधित इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना दी जाना सम्भव नहीं है सूचनार्थ प्रेषित है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नहीं है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 04.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए: अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( ज्ञाना राम )  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

2183-8  
28.12.17